Selling of confiscated Gold

96. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in view of the Chelliah Committee's recommendations, Government have decided to sell the gold confiscated and seized by various enforcement agencies like customs from smugglers and others by way of auction and to use the amount so raised alongwith the amount raised by way of disinvestment of public sector shares in clearing the public debts and raising the RBI dividends;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount of domestic public debt as at the end of 1991-92 and the extent of confiscated gold as available on 1st April, 1992 and at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) No, Sir.

(c) The amount of internal public debt and other liabilities of the Central Government at the end of 1991-92 (RE) stood at Rs. 3,17,379 crores. The quantity of confiscated gold held in Government accont as on 1.4.1992 and 19.11.1992 was 186.8 kg. and 1,071 kg. respectively.

बैंक कर्मियों की छंटनी

97. श्री राम नरेश यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय या आई०बी०ए० (बम्बई) के पास बैंक-कर्मियों की छंटनी करने सम्बन्धी कोई योजना लम्बित है जैसा कि दिनांक 26 सितम्बर, 1992 के दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो "एक लाख कर्मियों की छंटनी" सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली संभावित बेरोजगारी की समस्या के सम्बंध में कोई अध्ययन कराया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। बैंक कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में कोई योजना लम्बित नहीं है। तथापि, भारतीय बैंक संघ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए एक योजना की सम्भावना तथा प्रासंगिकता की जांच कर रहा है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में बैंकों का विलय

98. श्री राम नरेश यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 29 अगस्त, 1992 के दैनिक "इकानामिक टाइम्स" (अंग्रेजी) में "एस०बी०आई० एसोसिएट बैंक्स फार मरजर विद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद" शीर्षक से प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलय के मामले में सरकार के विचार क्या हैं; और

(ग) सभी सहयोगी बैंकों का विलय कब तक किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचार मांगे हैं। इस स्तर पर, प्रस्ताव पर निर्णय लेने सम्बन्धी किसी समय सीमा को बताना सम्भव नहीं होगा।

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र के निवेशकों को शेयरों में निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की योजना

99. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के निवेशकों को शेयरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?